



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

मई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 1979/प्राचाक 4, 1901

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 1979/ASADHA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न की जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मोबहन एवं परिवहन भवालय

(परिवहन कार)

प्रधिकाराद्य

मई दिल्ली, 25 जून, 1979

सं. का. नि. 399 (प्र) :—कलिप्य नियमों का निम्नलिखित मसीदा कलकत्ता पत्तन कान्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भर्तों की अवायायी) नियम, 1975 का संशोधन करते के लिए जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा बत्तन न्यास प्रधिकार, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उस धारा की उप-धारा (2) द्वारा यथापेक्षित उस सभी अधिकारियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रधायित होने की संभावना है और यह सुनित किया जाता है कि इस समितिका के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीस दिनों को अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उस मसीदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधायि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसीदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शाप्त होने वाली भाग्यियों या मुकाबों पर विचार करेगी।

नियमों का मसोदा

1. (1) इन नियमों का नाम कलकत्ता पत्तन का न्यासी मण्डल (न्या-सियों को शुल्क और भर्तों की अवायायी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को शुल्क होगे।

2. कलकत्ता पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भर्तों की अवायायी) नियम, 1975 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, प्रथम :—

“5 जो न्यासी संसद सदस्य ही या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भर्तों की अवायायी करना :—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद मदस्य अवधा राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संहित (निर्धारा निवारण) प्रधिकारियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के बाप्प (क) में यथापरिणायित प्रतिवूरक भर्तों की छोड़कर, जेसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हुक्मादार नहीं होगा, या उस भर्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का मदस्य इस प्रकार की निर्धारा के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारा निवारण के संबंध में राज्य में उस समय साधु किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हुक्मादार नहीं होगा।”

[पी० औ० एल०—१२/७८]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, 25th June, 1979

G.S.R. 399(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 which

the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

“5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[PGL-17/79]

सांकेतिक नियमों का निम्नलिखित मसौदा बन्धवी पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिए जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतीलीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम बन्धवी पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. बन्धवी पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5 जो न्यासी संसद सदस्य ही या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2प्र० और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संपद (निरहंता निवारण)

अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2के बाद (क) में यापारिशालित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जेसी भी स्थिति हो, यद्युक्ति भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरहंता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए निरहंता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता ही अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।”

[पी० जी० एल-१७/७९]

G.S.R. 400(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

“5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State: Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[PGL-17/79]

सांकेतिक नियम 401(अ)—कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा मद्रास पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतीलीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी।

नियमों का असौंदर्य

1. (1) इन नियमों का नाम मद्रास पतन का न्यासी मंड़त (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायपी) संशोधन नियम, 1979 है।
(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रयुक्त होने।
2. मद्रास पतन का न्यासी मंड़त (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायपी) नियम, 1975 में, नियम 2 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, प्रार्थतः—

“ 3 जो न्यासी मंडद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अवायपी करना :—

नियम 2 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संबंध सदस्य राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संबंध (निरहुता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यावापरिमाणित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरहुता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिये निरहुता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय जागू किसी भी कामने के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी० जी० एल०-17/79]

G.S.R. 401(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 2, the following rule shall be inserted, namely :—

“3. Payment of certain allowance to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rule 2 a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[PGL-17/79]

सा०जा०पि० 402(अ)—कलिय नियमों का निम्नलिखित मसौंदरीकोरिंग पतन का न्यासी मंड़त (न्यासियों की शुल्क और भत्तों की अवायपी) नियम, 1979 का संशोधन करने से सिये जिन्हें निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, प्रार्थतः—

का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त वालियों का प्रबोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा को उपधारा (2) द्वारा यावापरिमाणित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सुनित किया जाता है। कि इस प्रधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पेतालोंस दिनों की प्रवत्त समाप्त होने पर या उसके उक्ते बाद उक्त मसौंदरी पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिय समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौंदरी के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों का सुनावां पर विचार करेगी।

नियमों का असौंदर्य

1. (1) इन नियमों का नाम तूतीकोरिन पतन का न्यासी मंड़त (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायपी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रयुक्त होंगे।

2. तूतीकोरिन पतन का न्यासी मंड़त (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायपी) नियम, 1979 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, प्रार्थतः—

“ 4. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अवायपी करना :—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अवायपी राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संबंध (निरहुता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यावापरिमाणित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरहुता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिये निरहुता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय जागू किसी भी कामने के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।”

(पी०जी०हस०-17/79)

G.S.R. 402(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979 after rule 3 the following rule shall be inserted, namely :—

“4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance

as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[PGL-17/79]

संख्या 403(अ)—कलिप्य नियमों का निम्नलिखित मसौदा मार्गियों परत का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार महा पतन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्रियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उन धारा को उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनको उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस प्रधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसंमाप्त होने के से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुनावों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम मार्गियों परत का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होने।

2. मार्गियों परत का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“5. जो न्यासी संसद् सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना:

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद् सदस्य अधिकार राज्य विधान सभा का सदस्य भी हो, संसद् (निरहृता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के अध्य (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अर्थ किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरहृता के बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरहृता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अर्थ किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी.जी.एल. 17/79]

G.S.R. 403(E).—The following draft of certain rules to amend the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

“5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State: Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

संख्या 404(अ)—कलिप्य नियमों का निम्नलिखित मसौदा पारावीप परत का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1967 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पतन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्रियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उन धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस प्रधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसंमाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुनावों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम पारावीप परत का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होने।

2. पारावीप परत का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1967 में, नियम 3 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायगा अर्थात्:—

“4. जो न्यासी संसद् सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना:

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद् सदस्य अधिकार राज्य विधान सभा का सदस्य भी हो, संसद् (निरहृता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के अध्य (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अर्थ किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरहृता के लिए बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरहृता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अर्थ किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी.जी.एल. 17/79]

G.S.R. 404(E).—The following draft of certain rules to amend the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963

(38^o of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

“4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

सांकेतिक 405(प्र).—कर्तिपय नियमों का निम्नलिखित मर्यादा भूत पत्र न्यास (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की भवायारी) नियम, 1964 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने भूत पत्र न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपचारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपचारा (2) द्वारा यथाधर्मेष्ठि उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिकारी के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीस दिनों की अवधि मरात्त होने पर या उसके बाद उक्त मर्यादे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय मरात्त उक्त अवधि मरात्त होने से पूर्व उक्त मर्यादे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपलियों या सुनावों पर विचार करेगी।

नियमों का असाधारण

1. (1) इन नियमों का नाम भूत पत्र न्यास का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की भवायारी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होने।

2. भूत पत्र न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की भवायारी) नियम, 1964 में, नियम 4 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायगा, प्रथात् :—

“5. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की भवायारी करना :—

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य भव्यवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो, संसद (निरहंता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) को धारा 2 के खण्ड (क.) में यथा परिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर यदि कोई हो, तो जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरहंता निवारण के बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिये निरहंता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा।

[पी०जी०एल०-१७/७९]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 405(E).—The following draft of certain rules to amend the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

“5. Payment of certain allowance to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification”

[F. No. PGL-17/79]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

